MINISTÈRE
DE L'EUROPE
ET DES AFFAIRES
ÉTRANGÈRES
Liberté
Égalité
Fraternité

DIRECTION GENERALE DE L'ADMINISTRATION
ET DE LA MODERNISATION

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

Sous-direction de la Formation et des Concours

Bureau des concours et examens professionnels
RH4B

CONCOURS EXTERNE ET INTERNE POUR L'ACCÈS A L'EMPLOI DE SECRETAIRE DES AFFAIRES ETRANGÈRES (CADRE D'ORIENT) AU TITRE DE L'ANNÉE 2022

ÉPREUVES ÉCRITES D'ADMISSIBILITÉ

Jeudi 23 septembre 2021

HINDI

Durée totale de l'épreuve : 3 heures
Coefficient : 2
Toute note globale inférieure à 10 sur 20 est éliminatoire
Dictionnaire autorisé
Barème de notation : composition en hindi 12 points ; traduction en français 8 points

COMPOSITION EN HINDI

Composition en hindi à partir d'une question, rédigée dans cette même langue, liée à l'actualité
(350 mots avec une tolérance de plus ou moins 10%)

SUJET :

क्या पिछले कुछ दशकों में हुए आर्थिक विकास का लाभ भारतीय समाज के सभी वर्गों को मिला है?

MINISTÈRE
DE L'EUROPE
ET DES AFFAIRES
ÉTRANGÈRES
Liberté
Égalité
Fraternité

DIRECTION GENERALE DE L'ADMINISTRATION
ET DE LA MODERNISATION

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

Sous-direction de la Formation et des Concours

Bureau des concours et examens professionnels
RH4B

CONCOURS EXTERNE ET INTERNE POUR L'ACCÈS A L'EMPLOI DE SECRETAIRE DES AFFAIRES ETRANGÈRES (CADRE D'ORIENT) AU TITRE DE L'ANNÉE 2022

ÉPREUVES ÉCRITES D'ADMISSIBILITÉ

Jeudi 23 septembre 2021

HINDI

Durée totale de l'épreuve : 3 heures
Coefficient : 2
Toute note globale inférieure à 10 sur 20 est éliminatoire
Dictionnaire autorisé
Barème de notation : composition en hindi 12 points ; traduction en français 8 points

TRADUCTION EN FRANÇAIS

Traduction en français d'un texte rédigé en hindi

TEXTE AU VERSO

N.B. Ne traduire que l'extrait placé entre crochets

पीएम मोदी 'इंटरनेट शटडाउन' पर क्या दोहरी बातें कर रहे हैं?

विशाल शुकला, बीबीसी संवाददाता, BBC Hindi 16 juin 2021

क्या आपको दिल्ली की सीमाओं पर चल रहा किसान आंदोलन याद है? अगस्त, 2020 में शुरू हुआ यह आंदोलन इस साल की शुरुआत में चरम पर था और अब भी जारी है. इस दौरान कई ऐसे मौक़े भी आए, जब सरकार को इंटरनेट पर बैन लगाना पड़ा.

[भारत में यह कितना ज़्यादा होता है? इसे यूँ समझिए कि इंटरनेट शटडाउन का लेखा-जोखा रखने वाली वेबसाइट्स ने दावा किया कि 2021 के पहले 40 दिनों में ही सरकारें कम से कम 10 बार इंटरनेट बैन कर चुकी हैं.

फिर जब 2 फ़रवरी को इंटरनेशनल पॉप स्टार रिहाना ने ट्वीट किया कि 'किसान आंदोलन और इंटरनेट शटडाउन के बारे में बात क्यों नहीं हो रही है', तो जमकर हल्ला हुआ. विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि 'सिलेब्रिटीज़ के आरोप सही नहीं हैं और उन्हें ज़िम्मेदारी से ट्वीट करने चाहिए.'

इंटरनेट शटडाउन का ज़िक्र इसलिए किया जा रहा है, क्योंकि 2021 के जी-7 सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'ओपन सोसायटीज़ स्टेटमेंट' पर दस्तख़त किए हैं.

इसमें लिखा है कि 'राजनीति से प्रेरित इंटरनेट शटडाउन लोकतंत्र और आज़ादी के लिए ख़तरा है.' हालाँकि, इस पर साइन करते हुए मोदी अपनी आपत्तियाँ जताना भी नहीं भूले कि 'दुष्प्रचार और साइबर हमले' इस राह में बड़ी चुनौतियाँ हैं. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या भारत इंटरनेट शटडाउन के मामले पर दोहरा रवैया अपना रहा है?

क्या है जी-7 और ओपन सोसायटी?

जी-7 दुनिया के सात सबसे विकसित देशों- अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, फ़्रांस, इटली, जर्मनी और जापान का समूह है. इसे 1973 में वैश्विक समस्याओं से निबटने के लिए बनाया गया था.

इस साल जी-7 की अध्यक्षता ब्रिटेन के पास थी, जिसने कॉर्नवाल (Cornouailles/Cornwall) में आयोजित सम्मेलन में भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ़्रीका और दक्षिण कोरिया को बतौर मेहमान शामिल किया.

वहीं 'ओपन सोसायटी' की बात करें, तो यह फ़्रांसीसी दार्शनिक हेनरी बर्गसन (Henri Bergson) का दिया शब्द है, जिसका आशय बहुलतावादी समाज से होता है, जहाँ सभी के लिए बराबर अधिकार और आज़ादी होती है.

11 से 13 जून तक चले जी-7 सम्मेलन के आख़िरी दिन पहला सेशन 'ओपन सोसायटीज़' पर था, जिसमें पीएम मोदी बतौर लीड स्पीकर (conférencier principal) शामिल हुए.

सेशन के बाद दस्तावेज़ जारी किया गया, जिस में लिखा है, "हम एक नाज़ुक मोड़ पर खड़े हैं, जहाँ लोकतंत्र और आज़ादी के सामने बढ़ती निरंकुशता, चुनावी हस्तक्षेप, भ्रष्टाचार, आर्थिक दबाव, सूचनाओं में हेरा-फेरी, दुष्प्रचार, साइबर हमलों, राजनीति से प्रेरित इंटरनेट शटडाउन, मानवाधिकारों के उल्लंघन और हनन, आतंकवाद और हिंसक चरमपंथ का ख़तरा है. इन ख़तरों के बीच हम भविष्य के लिए एक खुली और समावेशी अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था बनाने के लिए मिलकर काम करेंगे, जो वैश्विक मानवाधिकारों और समान अवसरों को बढ़ावा देती है."

जी-7 सदस्यों समेत सम्मेलन में शामिल सभी मेहमान देशों ने इस पर दस्तख़त किए.**]**